# ओएसएम में गड़बड़ी पर हटाए गए सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव

## आइएएस लोखंडे प्रशांत नए चेयरमैन नियुक्त, वरुण भारद्वाज सचिव बनाए गए

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली**

आन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) के जरिए 12वीं के छात्रों के कराए गए मूल्यांकन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों को लेकर विवादों में घिरे सीबीएसई के खिलाफ सरकार मंगलवार को एक्शन में दिखी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश के बाद इसके चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। वरिष्ठ आइएएस लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन और इंडियन इंफोर्मेशन सर्विस के अधिकारी वरुण भारद्वाज को सचिव नियुक्त किया गया है।

इस बीच, ओएसएम से जुडे टेंडर मामले की जांच के लिए भी एक सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इसका जिम्मा कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की अध्यक्ष एस. राधा चौहान को सौंपा गया है। उन्हें एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। चौहान उत्तर प्रदेश कैडर की 1988 बैच की सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी हैं और केंद्र सरकार में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सचिव भी रह चुकी हैं। प्रशासनिक सुधार, मानव संसाधन प्रबंधन और सुशासन के क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। कमेटी को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह अपनी पसंद के किसी भी अधिकारी को अपने साथ नियुक्त कर सकती है। कमेटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कुछ और लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है।

सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय ने पहले ही ओएसएम के जरिए कराए गए मूल्यांकन से जुड़ी गड़बड़ी पर एक रिपोर्ट मांगी थी, जो सोमवार देर रात ही उसे सौंप दी गई थी। इस रिपोर्ट के बाद ही यह संकेत मिलने लगे थे कि जल्द ही दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। असली दोषी की पहचान तो जांच के बाद होगी, लेकिन सीबीएसई चेयरमैन और सचिव को अब कोई राहत न देने का फैसला हुआ। वैसे भी फिलहाल वही इस पूरी खामी के लिए चेहरा बने हुए थे।

सूत्रों की मानें तो पीएमओ इस बात से भी सीबीएसई से नाराज था कि वह गड़बड़ियों के सामने आने के बाद भी उसे ठीक करने में वह असफल रहा है। छात्रों को परेशान होना पड़ रहा है। पहले पुनर्मूल्यांकन का फैसला लेने में देरी और फिर बाद में पुनर्मूल्यांकन के लिए उसका पूरा सिस्टम भी फेल हो गया था। ( संबंधित समाचार, पेज-5 पर )

राहुल सिंह। फाइल

- एक सदस्यीय समिति करेगी टेंडर मामले की जांच, 30 दिन में देगी रिपोर्ट
- समिति की अध्यक्ष कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की चेयरपर्सन एस राधा चौहान होंगी

लोखंडे प्रशांत सीताराम। फाइल

### 13 मई को रिजल्ट आने के साथ ही शुरू हो गया था विवाद

सीबीएसई के मूल्यांकन से जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर यह पूरा विवाद 13 मई को 12वीं का रिजल्ट आने के साथ ही खड़ा हो गया था। छात्रों ने इस दौरान कम अंक मिलने की शिकायत की। इसे पहले सीबीएसई ने अनसुना कर दिया लेकिन जब यह मामला तूल पकड़ा तो सीबीएसई ने पुनर्मूल्यांकन और कापियों को मुहैया कराने का फैसला लिया। हालांकि इस दौरान कुछ छात्रों को दूसरों की कापियां दे दी गई थीं। छात्रों की आपत्ति के बाद गड़बड़ियों ने और तूल पकड़ा, जो अभी तक जारी है।

### संसदीय समिति के सामने 17 साल के छात्र सार्थक ने खोली गड़बड़ियों की पोल

**नई दिल्ली :** मूल्यांकन से जुड़ी गड़बड़ियों पर वैसे तो संसदीय समिति से जुड़े सदस्यों को सीबीएसई से सवाल करने थे और उन्होंने किए भी लेकिन समिति के सामने पेश हुए 12वीं के छात्र सार्थक ने ओएसएम से जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर जिस तरह के सवाल खड़े किए, उससे समिति के मौजूद सदस्य दंग रह गए। समिति के सदस्यों ने न सिर्फ मेज थपथपाई बल्कि सीबीएसई के अधिकारियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि कुछ इनसे सीखो। वहीं, सार्थक के सवालों से सीबीएसई पूरी तरह से निरुत्तर दिखी। (पेज-5)

# नेपाल से सीमा विवाद में तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं : भारत

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली**

- **विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग पर भारत ने किया इन्कार**
- **विदेश मंत्रालय ने कहा- यह पूरी तरह द्विपक्षीय मुद्दा, किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं बनती**

भारत-नेपाल सीमा विवाद पर बयान देकर प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह बुरी तरह से घिरते नजर आ रहे हैं। सीमा विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की उनकी मांग पर भारत ने साफ इन्कार कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह पूरी तरह द्विपक्षीय मुद्दा है और इसमें किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं बनती। 'नेपाल द्वारा भी भारत की जमीन पर अतिक्रमण' संबंधी बयान के बाद बालेंद्र शाह को लगातार विपक्षी दलों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को कहा, ''भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद के सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए द्विपक्षीय तंत्र पहले से मौजूद हैं। यह स्पष्ट होना चाहिए कि इस द्विपक्षीय मुद्दे में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।'' पीएम शाह ने रविवार को संसद में कहा था कि भारत के साथ बातचीत के अलावा नेपाल चीन और ब्रिटेन से भी संपर्क में है। उन्होंने कहा, ''चूंकि यह विवाद ब्रिटिश काल से जुड़ा है, इसलिए ब्रिटेन को भी इसमें शामिल होना चाहिए।'' जायसवाल ने कहा कि भारत-नेपाल की लगभग 98 प्रतिशत सीमा पहले ही चिह्नित की जा चुकी है और विवादों का समाधान निकाला जा चुका है। बाकी कुछ हिस्सों में विवाद है, जिनमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और

नई दिल्ली में मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल। एएनआइ

कालापानी शामिल हैं। भारत इन क्षेत्रों को हमेशा उत्तराखंड का अभिन्न अंग मानता रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि गंडक नदी के रास्ते में बदलाव और कुछ जगहों पर अतिक्रमण के कारण यह स्थिति बनी है। दोनों देश संयुक्त रूप से इन अतिक्रमणों का नक्शा तैयार कर रहे हैं। इस मामले में नेपाल के विदेश मंत्रलाय ने एक बयान भी जारी किया है। जायसवाल ने कहा, ''हमने नेपाल के विदेश मंत्रालय के बयान को देखा है और इस पूरे मामले का समाधान केवल द्विपक्षीय बातचीत से ही होगा।''

# वेनेजुएला के साथ दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी की ओर भारत

## अंतरिम राष्ट्रपति रोड्रिगुएज गोम्स 3 से 7 जून तक भारत यात्रा पर

### भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है वेनेजुएला

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली**

वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिगुएज गोम्स 3 से 7 जून 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रही हैं। पहले वे एक जून को इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस समिट में शामिल होने वाली थीं, लेकिन समिट टल जाने के कारण यह यात्रा कार्यकारी रूप में हो रही है। रोड्रिगुएज गोम्स विदेश मंत्री, अर्थव्यवस्था एवं वित्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं सूचना तथा परिवहन मंत्रियों के साथ आ रही हैं, जो बताता है कि भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए वह बेहद गंभीर हैं। वैसे यह उनकी छठी भारत यात्रा होगी। इसके पहले विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति के तौर पर वह पांच बार भारत आ चुकी हैं। वह सत्य श्री साई बाबा की भक्त हैं और पूर्व में दो बार आंध्र प्रदेश स्थित पुत्तपर्थी (साई बाबा का आश्रम) का दौरा कर चुकी हैं।

डेल्सी एलोइना रोड्रिगुएज गोम्स। फाइल

बहरहाल, इस बार उनकी इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक ऊर्जा समझौता होने की संभावना बताई जा रही है। वेनेजुएला पर अमेरिकी नियंत्रण समाप्त होने के बाद भारत ने वहां से तेल आयात में भारी वृद्धि कर दी है। पारंपरिक तौर पर भारत वेनेजुएला से तेल खरीदता रहा है लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से इसमें बाधा आती रही है। पश्चिम एशिया की मौजूदा अस्थिरता व हार्मुज जलडमरूमध्य की बंदी के कारण रूस के बाद वेनेजुएला के कच्चे तेल की खरीद भारत बढ़ा चुका है। अप्रैल 2026 में भारत ने 1.25 करोड़ बैरल (छह वर्षों में सर्वाधिक) वेनेजुएला से क्रूड आयात किया। मई में यह बढ़कर औसतन 4.17 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया, जिससे वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। जानकारों के मुताबिक महंगा होने के बावजूद वेनेजुएला भारत के लिए अच्छा विकल्प साबित हो रहा है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर आपूर्ति बाधित है और भारतीय रिफाइनरियां भारी-उच्च सल्फर वाले वेनेजुएला क्रूड को प्रोसेस करने में सक्षम हैं।

### पीएम मोदी से द्विपक्षीय चर्चा करेंगी अंतरिम राष्ट्रपति

अंतरिम राष्ट्रपति यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से द्विपक्षीय चर्चा करेंगी। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार एवं निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विस्तृत बातचीत होगी। भारत सरकार की तेल कंपनियां वेनेजुएला में ऊर्जा क्षेत्र में पहले से ही निवेश करती रही हैं। अब वहां बेहतर माहौल होने से ये कंपनियां वहां निवेश बढ़ाने को इच्छुक हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और आटोमोबाइल क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों का दौरा करेगा ताकि भारतीय तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझा जा सके और सहयोग के नए अवसर तलाशे जा सकें। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होने तथा दोनों देशों के बीच विविध क्षेत्रों में गहरे सहयोग की उम्मीद है।

श्री राम शा

shriramshaw
@nda.jagra
n.com


आजकल

# वैश्विक मंच पर उभरता भारत

हाल में संपन्न प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पांच देशों–यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नार्वे और इटली की यात्रा केवल एक कूटनीतिक दौरा नहीं, बल्कि 21वीं सदी में भारत की वैश्विक महाशक्ति बनने की आकांक्षा का एक जीवंत घोषणापत्र है। यह यात्रा भारत के लिए सामरिक सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता, ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और आर्थिक संप्रभुता को मजबूत करने का एक ऐसा अवसर बनकर उभरी है, जिसका प्रभाव आने वाले कई दशकों तक महसूस किया जाएगा

पश्चिम एशिया में तनाव के बीच यूएई के साथ मिलकर अपनी ऊर्जा आपूर्ति लाइन को सुरक्षित करता भारत। फाइल

वैश्विक राजनीति और अर्थनीति आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां पुराने समीकरण बदल रहे हैं, और नए गठबंधनों का उदय हो रहा है। अमेरिकी विदेश नीति में आए बदलावों, रूस-यूक्रेन युद्ध के लंबे खिंचते संकट और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच पूरी दुनिया नए और भरोसेमंद साझेदारों की तलाश में है। ऐसे नाजुक और ऐतिहासिक मोड़ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पांच देशों - संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), नीदरलैंड्स, स्वीडन, नार्वे और इटली की यात्रा केवल एक कूटनीतिक दौरा नहीं, बल्कि 21वीं सदी में भारत की वैश्विक महाशक्ति बनने की आकांक्षा का एक जीवंत घोषणापत्र है। यह यात्रा भारत के लिए सामरिक सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता, ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और आर्थिक संप्रभुता को मजबूत करने का एक ऐसा त्रिवेणी संगम बनकर उभरी है, जिसका प्रभाव आने वाले कई दशकों तक महसूस किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस पांच दिवसीय यात्रा का पहला पड़ाव संयुक्त अरब अमीरात था, जो वैश्विक तेल बाजार में आए भूचाल और अमेरिका इजरायल-ईरान संघर्ष के कारण बेहद संवेदनशील समय पर हुआ। जब पूरा पश्चिम एशिया अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, तब भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को एक मजबूत ढाल प्रदान की। यह तथ्य है कि भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग दसवां हिस्सा यूएई से आयात करता है और वह यूएई की तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का सबसे बड़ा खरीदार भी है।

इस यात्रा के दौरान हुए महत्वपूर्ण समझौते भारत की दूरदर्शिता को दर्शाते हैं। 'इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड' और यूएई की 'एडनाक' के बीच हुए समझौते के तहत यूएई भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व में कच्चे तेल की आपूर्ति को बढ़ाकर तीन करोड़ बैरल करेगा। दोनों देशों ने भारत में रणनीतिक गैस रिजर्व स्थापित करने की संभावनाओं पर सहमति जताई, ताकि भविष्य में किसी भी वैश्विक आपूर्ति संकट से देश को बचाया जा सके। यूएई ने भारत में पांच अरब डालर (लगभग 41 हजार करोड़ रुपये) के नए निवेश की प्रतिबद्धता जताई, जो दोनों देशों के बीच पहले से चल रहे 85 अरब डालर के द्विपक्षीय व्यापार को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यात्रा का अगला चरण यूरोप के नवाचार और तकनीक के गढ़ नीदरलैंड्स और स्वीडन की ओर था। वर्तमान समय में यूरोप चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता को कम करना चाहता है और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अपनी रक्षा और ऊर्जा प्राथमिकताओं को नए सिरे से तय कर रहा है। ऐसे में यूरोप भारत को एशिया में सबसे भरोसेमंद लोकतांत्रिक साझेदार के रूप में देख रहा है। नीदरलैंड्स की यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण तकनीकी क्षेत्र, विशेषकर सेमीकंडक्टर मिशन रहा। नीदरलैंड्स दुनिया की सबसे उन्नत लिथोग्राफी मशीनें बनाने वाली कंपनी एएसएमएल का घर है, जिसके बिना आधुनिक सेमीकंडक्टर चिप निर्माण असंभव है। इस यात्रा के दौरान गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जो भारत को वैश्विक चिप निर्माण का केंद्र बनाने के सपने को साकार करेगा। दोनों देशों ने बैटरी, इलेक्ट्रानिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आवश्यक 'क्रिटिकल मिनरल्स' (महत्वपूर्ण खनिजों) की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समझौते किए। जल प्रबंधन और ग्रीन हाइड्रोजन में डच महारत का लाभ उठाने पर भी सहमति बनी।

गोटेबर्ग में स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन के साथ हुई बैठक ने भारत-यूरोप संबंधों को नया आयाम दिया। भारत और स्वीडन के संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' के स्तर पर ले जाया गया। दोनों देशों ने 'संयुक्त नवाचार साझेदारी 2.0' और 'भारत-स्वीडन प्रौद्योगिकी एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कारिडोर' की शुरुआत की। अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का संकल्प लिया गया।

यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली पहुंचे। मोदी और मेलोनी के बीच द्विपक्षीय बैठक में भावी रणनीतिक साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा हुई। भारत-इटली संयुक्त कार्य योजना 2025-29 इस साझेदारी को एक व्यावहारिक एवं भविष्योन्मुखी ढांचा प्रदान करती है। साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत-ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा हुई। 2027 में 'इटली-इंडिया ईयर आफ कल्चर एंड टूरिज्म' मनाने की योजना का भी एलान किया, जिसका मकसद दोनों सभ्यताओं के लोगों के बीच रिश्तों को और मजबूत करना है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पांच देशों की यात्रा ने अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के बीच भारत को लेकर एक अभूतपूर्व विश्वास पैदा किया है। आज जब वैश्विक बाजार में अनिश्चितता और मंदी का माहौल है, निवेशक अत्यधिक सतर्क हैं और पूंजी सुरक्षित स्थानों की तलाश में है, तब भारत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ) को आकर्षित करने में सफल रहा है। ज्ञात हो कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश केवल धन नहीं लाता, यह बिना ब्याज की ऐसी पूंजी है, जो देश में आधुनिक तकनीक लाती है, विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करती है और बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसरों का सृजन करती है।

# सामने आईं चीन की रणनीतिक सीमाएं

धीरज यादव

भू-राजनीति, रक्षा और रणनीतिक मामलों के जानकार


हालिया वैश्विक संघर्षों ने दुनिया के सामने शक्ति संतुलन की एक नई तस्वीर पेश की है। जहां एक ओर अमेरिका ने ईरान की सैन्य शक्ति और नेतृत्व को भारी क्षति पहुंचाई है, वहीं दूसरी ओर खुद को सुपरपावर बताने वाले चीन की रणनीतिक निष्क्रियता ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की संतुलित कूटनीति कारगर साबित हो रही है। चीन का रणनीतिक साझेदार ईरान आज अपने इतिहास के एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है।

भौगोलिक रूप से भी दोनों देशों के बीच केवल पाकिस्तान है, इसके बावजूद, चीन न तो ईरान को आधुनिक हथियारों की पर्याप्त आपूर्ति कर पाया और न ही उसके सैन्य बलों को ठोस सैन्य प्रशिक्षण या रणनीतिक सहायता दे पाया। यह विफलता इसलिए अधिक चौंकाने वाली है, क्योंकि ईरान तथा अमेरिका-इजरायल के बीच युद्ध के संकेत पिछले वर्ष 12-दिवसीय लड़ाई से ही मिल गए थे और दोनों पक्षों के बीच शत्रुता दशकों पुरानी है। चीन के विपरीत अमेरिका हजारों मील दूर से अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार वह 13000 से अधिक लक्ष्यों पर हमले कर ईरान की कमर तोड़ चुका है।

अमेरिका ने ईरान के शीर्ष नेतृत्व, सैन्य शक्ति और परमाणु ढांचे को भारी क्षति पहुंचाई है। अमेरिका, इजरायल और अन्य खाड़ी देशों को भी नुकसान हुआ है, पर वह तुलनात्मक रूप से काफी कम है। यह सही है कि अमेरिका इस समय कई मोर्चों पर एक साथ उलझा हुआ है- जहां एक ओर वह ईरान के साथ युद्ध में फंसा है, वहीं दूसरी ओर क्यूबा की तेल नाकाबंदी कर रखी है और 2022 से यूक्रेन को निरंतर समर्थन भी दे रहा है। इसके बावजूद चीन ने ताइवान के एकीकरण के लिए किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई से परहेज किया है। यह अमेरिका और चीन की सैन्य क्षमताओं के बीच बड़े अंतर को दर्शाता है। यह चीन की उस छवि को धूमिल करता है जिसमें उसे अमेरिका के विकल्प के रूप में देखा जा रहा था।

अमेरिका एक-एक करके चीन के सहयोगी देशों को परास्त कर एवं उनमें सत्ता परिवर्तन कर अपने सहयोगियों में बदल रहा है। अन्य देश देख रहे हैं कि चीन के हथियारों और उसकी रणनीतिक साझेदारी पर भरोसा करना कितना जोखिम भरा हो सकता है। इससे साफ हो रहा कि अब वे अमेरिकी एवं यूरोपीय हथियार ज्यादा खरीदेंगे और हर परिस्थिति में अमेरिका से अच्छे रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करेंगे। ब्रिक्स सदस्य और कच्चा तेल उत्पादित करने वाले खाड़ी देश भी डी-डालराइजेशन जैसी किसी पहल का समर्थन करने से कतराएंगे।

इस समय भारत की राष्ट्रहित सर्वोपरि की नीति अत्यंत तर्कसंगत है- अमेरिका से अनावश्यक टकराव नहीं, लेकिन जहां राष्ट्रहित हो वहां दृढ़ता से खड़े रहना है। भारत ने अमेरिकी सैन्य कारवाई की खुली आलोचना नहीं की, परंतु साथ ही ईरान के युद्धपोत आइआरआइएस लवान को कोच्चि में शरण दी और उसके 100 से अधिक नौसैनिकों को आर्मेनिया के रास्ते सुरक्षित वापस भी भेज दिया। इस संतुलित नीति का ही परिणाम है कि आज भारत के अमेरिका से भी अच्छे संबंध हैं और ईरान ने भी 18 अप्रैल को हार्मुज जल मार्ग को दोबारा बंद करने से पहले जिन गिने चुने मित्र देशों के जहाजों को गुजरने की अनुमति दी थी उनमें भारत भी शामिल था। यह भारत की संतुलित विदेश नीति का प्रमाण है।

भारत अब संतुलित कूटनीति से अपने राष्ट्रीय हितों को साध रहा है यही रणनीतिक स्वायत्तता है और यही भारत को भविष्य में एक बड़ी शक्ति बनने की ओर अग्रसर कर रही है।

# CBSE officials transferred, panel to probe OSM tender

Centre replaces CBSE Chairman, Secretary, appoints one-person body to investigate procurement of services for OSM portal; transfers 'cover up' to spare political leadership, say Opposition leaders

**The Hindu Bureau**
NEW DELHI

With the Central Board of Secondary Education (CBSE) facing flak for its controversial new on-screen marking (OSM) system, the Centre on Tuesday replaced the Board's Chairman and Secretary.

It also set up a one-member committee to inquire into the Board's procurement of services for the marking process. The committee, chaired by S. Radha Chauhan, chairperson of the Capacity Building Commission, has been asked to submit its report within a month. As per the Cabinet Appointments Committee, senior IAS officer Lokhande Prashant Sitaram will be the new CBSE Chairperson, replacing Rahul Singh, who has been moved to the Agriculture Ministry. Varun Bhardwaj, a Director in the Education Ministry, will take over as CBSE Secretary, replacing Himanshu Gupta, who has been prematurely repatriated to his parent cadre in the Home Ministry.

Calling the transfers "a cover up", the Congress said the move was an attempt to fix accountability on bureaucrats rather than the political leadership, and reiterated its demand that Union Education Minister Dharmendra Pradhan resign or be sacked.

CONTINUED ON
» PAGE 12

Youth Congress members protest seeking the resignation of the Union Education Minister in Mumbai on Tuesday. EMMANUAL YOGINI

## Re-evaluation portal open; glitches reported

**NEW DELHI**

After the CBSE opened its portal for submitting re-evaluation requests on Tuesday following a delay of a day, multiple Class 12 students reported technical errors and discrepancies. » PAGE 13

## Teen briefs House panel on issues in CBSE OSM tender

**NEW DELHI**

Sarthak Sidhant, a 17-year-old student, on Tuesday presented his findings on alleged anomalies in the OSM tender process before a Parliamentary Standing Committee. » PAGE 13

# The 'harvest' China wants is one India cannot afford

When Luo Zhaohui, then China's Ambassador to India, revived the idea of an "early harvest" in India-China boundary negotiations in 2017, India responded with scepticism. The proposal – to settle the Sikkim boundary in isolation from the three other sectors – was an asymmetric concession dressed up in the language of progress. India has resisted it. There is now a gnawing doubt as to whether it can hold that position. The trigger for this piece is a former border negotiator's concern that India might "stumble" into a damaging course of action under Chinese pressure and driven by the temptation to project contrived progress. Diplomacy that trades long-term strategic interests for short-term optics is self-defeating.

**Ashok K. Kantha**

Former Ambassador to China, Subhas Chandra Bose Chair Professor of International Relations, Chanakya University, and Distinguished Fellow with the Vivekananda International Foundation

### New Delhi must be cautious

The readout issued by the Ministry of External Affairs (MEA) on the 24th round of the Special Representatives' Dialogue on the Boundary Question between India and China (on August 19, 2025) between National Security Adviser Ajit Doval and Chinese Foreign Minister Wang Yi recorded India's agreement to "set up an Expert Group ... to explore an early harvest in boundary delimitation in the India-China border areas". China's own readout was more pointed: it used the term "demarcation" rather than "delimitation" and spoke of "launching boundary demarcation negotiations in sectors where conditions are ripe."

The MEA press release on the 35th Meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs, held in Beijing on May 27, 2026, mentions that the two sides "discussed issues pertaining to delimitation, border management, mechanism building and cross-border cooperation" and "agreed to work together to make substantive preparation" for the next SRs' meeting. The reference to 'delimitation' is significant as it suggests follow-up discussions on the understanding "to explore Early Harvest in boundary delimitation".

The cornerstone of Special Representative negotiations is the Agreement on Political Parameters and Guiding Principles, signed on April 11, 2005. Article III explicitly envisages "a package settlement" covering all sectors of the India-China boundary. It establishes a three-step process: first political parameters, then a framework for a final settlement, then delineation and demarcation. Demarcation – placing physical markers on the ground – comes last, not first. China's proposal to begin demarcation in a single "ripe" sector inverts this sequence and, in effect, asks India to abandon the package architecture in exchange for the appearance of progress. India should decline.

Why does the package settlement matter so much? Because the four sectors of the India-China boundary are strategically interlinked, requiring give and take across sectors. It also guards against China extracting concessions sector by sector. An early harvest in Sikkim, where India holds comparative geographical advantage, would let Beijing bank a settlement on its preferred terms while leaving the other three sectors unresolved.

Diplomatic optics must not dictate India's boundary negotiations with China

### The Sikkim stakes

The Sikkim Sector boundary is not, as sometimes claimed, a simple matter. Clashes at Nathu La and Cho La in 1967, with heavy casualties, showed how sharp these differences are. Article I of the 1890 Great Britain-China Convention identifies "Mount Gipmochi on the Bhutan frontier" as the starting point of the Sikkim-Tibet boundary, but it is preceded by an assertion that the boundary "shall be the crest of the mountain range separating the waters flowing into the Sikkim Teesta and its affluents from the waters flowing into the Tibetan Mochu". China reads the article as placing the trijunction at Gipmochi. India and Bhutan hold that the trijunction lies at Batang La, some 6.5 kilometres to the north, on the watershed – which is the operative geographical principle in Article I.

Zompelri (or Jampheri) Ridge adjoining Geymochen commands a direct view of the Siliguri Corridor, the narrow strip connecting mainland India to its northeastern States. Any settlement implicitly endorsing the Gipmochi trijunction would hand China a legal instrument to press its claim to the very edge of the Himalayas, exposing the Corridor. The Chinese objective is to deepen and widen its Chumbi Valley and increase pressure on India's most acute territorial vulnerability.

The Doklam dimension reinforces this concern. Since 2017, China has systematically consolidated its position in western Bhutan – building roads and military facilities, constructing villages including Pangda on the Amo Chu river, and developing routes to the Jampheri Ridge that bypass the 2017 Doklam standoff site. A Sikkim settlement would immediately be leveraged by Beijing to step up pressure on a vulnerable Bhutan to settle its boundary with China. India and China have agreed that trijunction points must be finalised in trilateral consultation with all countries concerned. Even if the trijunction point is left out, China could force Bhutan to settle the rest of the disputed boundary on its own terms and present India with a *fait accompli* in Doklam.

Since the Eastern Ladakh transgressions of 2020, China has pursued multiple pressure tracks simultaneously: military consolidation along the Line of Actual Control (LAC), steady resurrection of the "Zangnan" (South Tibet) narrative to describe Arunachal Pradesh, renaming of places in Arunachal Pradesh, and expansion of "border defence villages" close to India-China LAC.

The resumption of Special Representative talks is welcome, but dialogue must be conducted with strategic clarity, not under diplomatic pressure or for the optics of progress. Three principles should guide India's approach.

First, hold the 2005 Agreement's framework firm. The Expert Group agreed upon in August 2025 must not become a vehicle for an early harvest in Sikkim. Agreeing to "explore" is not a commitment to accept. India should reject a standalone Sikkim delimitation or demarcation exercise.

Second, make peace and tranquillity on the LAC the non-negotiable condition of progress. China has periodically attempted to delink border management from the broader relationship; India has resisted this, and should continue to do so. Unilateral alterations to the LAC cannot be normalised. Indeed, the so-called "buffer zones" in Eastern Ladakh must not be allowed to persist.

Third, press for genuine political engagement on a comprehensive settlement. Decades of talks have shown that the respective narratives cannot be reconciled through legal arguments. The 2005 Agreement recognised this: it called for a political settlement that would "safeguard the vital interests of both countries" and set out principles such as the two sides "safeguard(ing) due interests of their settled populations in the border areas". Any breakthrough requires political will on both sides. India should press for meaningful boundary negotiations, not paper over the lack of progress with working groups. The test of China's seriousness will be whether it is prepared to engage on the framework for a comprehensive settlement – and whether it is prepared to hold the LAC stable while that engagement proceeds. Absent those conditions, the Special Representative process risks becoming what it has sometimes been before: a forum for managing appearances while China improves its position on the ground.

### Stay the course

In boundary talks, China has a track-record of cherry-picking and resiling from formal commitments, as it did in the case of an explicit agreement to arrive at a common understanding of the LAC after exchanging maps showing the entire alignment. India must prevent the Agreement On the Political Parameters and Guiding Principles for the Settlement of the India-China Boundary Question from meeting a similar fate. If peace and tranquillity on the LAC is the foundation for rebuilding India-China relations, the 2005 Agreement is the road map for resolving the boundary question. India has nothing to gain from an early harvest limited to Sikkim and must maintain its negotiating space through a comprehensive negotiation. India cannot afford a shortcut to a destination that suits China.

# The future of India's chip industry

A new NITI Aayog report says India's semiconductor ecosystem is not yet equipped to fully meet domestic demand, while stressing the need to strengthen local manufacturing, as geopolitical pressures could potentially disrupt the electronics supply chain

**EXPLAINER**

**Aroon Deep**

NITI Aayog's Frontier Tech Hub released a report last week that had two main messages: first, that India faces steep challenges in developing world-class semiconductor manufacturing capabilities, and second, that national interest necessitated pursuing this field doggedly regardless of those difficulties.

The Union government has made chipmaking a priority, since semiconductors are a part of nearly all electronics, from consumer gadgets to defence gear. Yet, India does not have a single fabrication unit, with the first expected to open in Dholera, Gujarat by 2028, with a total of ten in various stages of development. Multiple semiconductor packaging and testing facilities have been generously subsidised and supported by the Union government (as well as some State governments), through initiatives like the India Semiconductor Mission (ISM).

The ISM is a ₹76,000 crore corpus, and it is almost fully earmarked to projects across semiconductor fabs, incentives for component manufacturing, and bulk subscriptions to industry-grade semiconductor design applications for students and academia. While the most cutting edge and ambitious projects – fabs – have received capital subsidies of upwards of 50%, other projects have received production- or output-linked incentives.

The report, titled 'Future of India's Semiconductor Industry', reiterates that these are yet early days for the semiconductor industry, since even chips used in domestic electronics assembly operations are largely sourced from outside the country. "India's local ecosystem is not ready to fully meet domestic demand for semiconductors," the report said. But it insisted that there was still a need to manufacture locally, as geopolitical pressures like a disaster in Taiwan could massively disrupt the electronics supply chain. "As many semiconductor parts used in defence systems are produced outside India, deploying them in our aerospace and defence programmes is increasing threats to national security," the report adds.

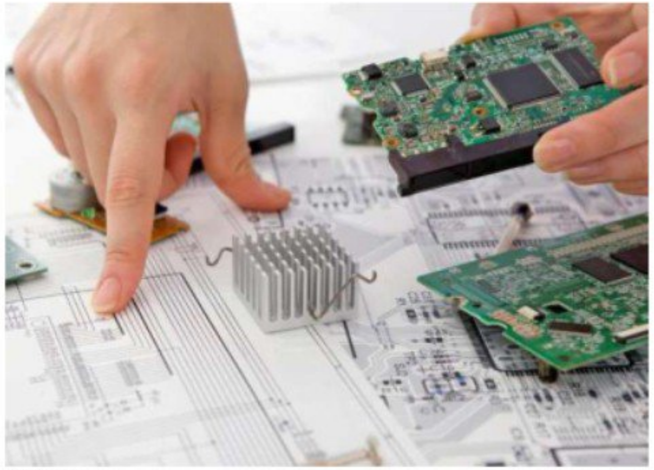

GETTY IMAGES

The sector "requires sustained, mission-mode commitment over a decade or more," the report said.

**Fab gestation**

The report points to several challenges in this indigenisation process, not least of which is the time involved. "Typically, fab units require four to five years before commencing production," the report points out. "During the gestation phase, these units need to invest in purchasing more than 50 specialised equipment from global players. Even after the production is over, processes like yield optimisation and reliability test take several quarters before chips reach the market." Developing talent to work in these fabs is also, as a result, time consuming, the report says.

The report urges the government to work on "building sovereign design and research capabilities, R&D excellence and harnessing agentic AI for semiconductor engineering," since "building deep capabilities" in materials sciences and silicon designing will "move India from a services-led design base to a creator of differentiated IP, architectures and integration technologies that define next generation systems."

**Capital investment**

While the details on the second phase of the India Semiconductor Mission are yet to be revealed, the report pegs the necessary capital expenditure from the state at $45-60 billion over a period of ten years. This amount should, however, be spent on projects where the risk is less and "bankability" can assure returns to investors, the report warns. This translates to a shift away from directing public funds towards frontier chips, whose transistors are the smallest – 3 to 7 nanometres – and towards "mature, advanced–aligned with strategic relevance–as well as compound nodes," the report says.

The report is key in understanding the potential scope of ISM 2.0, since its ambition is defined and largely stays out of big-ticket frontier fab projects. It advocates, for instance, "selective depth, capital efficiency and system-level differentiation, rather than attempting to replicate the full global manufacturing spectrum."

For instance, packaging, which is among the last steps of a chipmaking process, and less expensive and complex than fabrication, is identified as a "core production pillar, not a downstream activity" in the report. The report calls for "[r]apid import substitution in high volume domestic segments".

**Trusted partners**

The report implies that China is an adversary in chipmaking in spite of the recent thaw in relations. In a list of "priority partners," the report highlights the U.S., Japan, the European Union, and South Korea as partners with whom to work to get "access to critical tools, equipment servicing and lifecycle support," and to take advantage of "India's market scale, talent base and packaging capacity."

"With sustained commitment and strategic clarity, India can build a competitive semiconductor ecosystem that strengthens economic resilience and positions the nation as a key player in the future of advanced technology," the report concludes. IT Secretary S. Krishnan welcomed the report as a "structured, actionable framework," and said in a foreword that, "India is well positioned to convert its semiconductor ambition into enduring industrial and strategic reality".

**THE GIST**

- The Union government has made semiconductor manufacturing a priority, but India does not yet have a fabrication unit. A recent report by NITI Aayog's Frontier Tech Hub underscores the need to bolster local manufacturing.
- The report urges the government to work on 'building sovereign design and research capabilities, R&D excellence and harnessing agentic AI for semiconductor engineering'.